

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 23 अक्टूबर 2024, समय 1810 (10 मिनट))

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में पराली जलाने पर सज़ा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा।
- केन्द्र सरकार ने भारत ब्रैंड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण शुरू किया।
- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पराली जलाने के मामले में अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं।
- हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनज़र गुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12 हज़ार रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि बीजेपी वोट के लिए नहीं व्यवस्था के लिए काम करती है।
- हरियाणा में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 सितंबर तक महिला विरुद्ध अपराधों में भारी कमी दर्ज की गई। दुष्कर्म के मामलों में 20.5 प्रतिशत और छेड़छाड़ के मामलों में 33.1 प्रतिशत की कमी आई।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में पराली जलाने पर सज़ा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम, कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाये बिना लागू किया गया। केन्द्र की ओर से अपर महाधिवक्ता ऐश्वर्य भाटी ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि दस दिन के अंदर नियम तय कर लिये जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर पंजाब एवं हरियाणा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने कहा कि यदि ये सरकारें कानून लागू करने के प्रति गंभीर होती तो इसके परिणाम सामने आते। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण सचिव और अपर मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि नियमों के उल्लंघन पर लगभग एक हजार अस्सी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं लेकिन राज्य ने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूल किया है।

केन्द्र सरकार ने आज भारत ब्रैंड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ - नेफेड के माध्यम से यह बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केन्द्रीय भण्डार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई-कॉमर्स माध्यम से 70 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। इसके अलावा चना 58 रुपये प्रति किलो, भारत मूंग दाल 107 रुपये प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले अलनीनो प्रभाव के वजह से चना दाल से आयात शुल्क हटा दिया था। अलनीनो प्रभाव के कारण पिछले वर्ष इसका उत्पादन कम हुआ था।

श्री जोशी ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड किसानों के साथ उनकी पूरी पैदावार की खरीद के लिए समझौते पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष में दस हजार करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इस राशि का उपयोग मंहगाई पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा द्वारा ई वी एम पर सवाल उठाने और इस मामले में अदालत में जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीतती है वहां ई वी एम कैसे ठीक होती है। उन्होंने कहा कि बी जे पी की जीत पर यह चुनाव आयोग और ई वी एम पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। श्री विज आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कुमारी सैलजा द्वारा हरियाणा में लगाए जा रहे समाधान शिविर पर सवाल उठाने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के काम करने पर भी उन्हें एतराज है। पहलवान साक्षी मलिक द्वारा आंदोलन के लिए उकसाने वाले बयान पर श्री विज ने कहा कि वह खेल मंत्री रहे हैं, उन्हें खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, उन्हें अपनी राजनीति व दूसरों की राजनीति का पता है। मगर, उन्हें खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस विधायक द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के मामले में दिए गए बयान पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने कहा है कि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी और कहीं अनियमितता सामने आएगी तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, पराली जलाने के मामले में मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में है और जो आदेश दिए जा रहे हैं उस पर अमल भी किया जा रहा है। वहीं, किसानों द्वारा इस

मामले में अधिकारियों को दी जा रही धमकी पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार या अधिकारी जो भी कर रहे हैं वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक कर रहे हैं और आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए।

हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस तरह राज्य सरकार के ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 15 करोड़ 75 लाख रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि वितरित की जाएगी। अग्रिम राशि की अधिकतम 10 मासिक किश्तों में अदायगी की जा सकेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के आवास संत कबीर कुटीर पर आज आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कई प्रमुख साधू संतों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री और संत समाज के लोगों ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जनता के साथ किए गए वादों के अनुसार काम कर रही है। बीजेपी वोट के लिए नहीं व्यवस्था के लिए काम करती है।

वहीं सरकार के कामकाज से संतुष्ट संत समाज ने उनकी सराहना की। स्वामी शाश्वता नंद गिरि जी महाराज ने कहा:

हरियाणा में अपराध लगातार कम हो रहा है। हरियाणा में अपराध एवं अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 सितंबर तक महिला विरुद्ध अपराधों भारी कमी आई है। दुष्कर्म के मामलों में 20.50 प्रतिशत और छेड़छाड़ के मामलों में 33.10 प्रतिशत की कमी आई है। डकैती के मामलों में 42 प्रतिशत, लूटपाट में 33.10 प्रतिशत और हत्या के मामलों में 6.89 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में अपराधियों की साँठ गांठ खत्म करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल ने इस वर्ष अब तक 179 अति वांछित ईनामी बदमाशों, 45 गैंगस्टरों तथा गंभीर अपराधों में संलिप्त 309 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष कार्य बल की 8 टीमों का गठन किया गया है जिन्हें विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि अपराध व अपराधियों की

कमर तोड़ने के उद्देश्य से आप्रेशन आक्रमण के तहत वर्ष-2024 में अब तक पुलिसकर्मियों की 12 हजार 160 टीमों द्वारा 3 हजार 943 मामले दर्ज करते हुए 7 हजार 586 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नम्बर 1 8 0 0 - 1 1 - 7 8 0 0 पर कार्यक्रम के लिए परसों शाम तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। **माइगाँव, नमो एप** पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर "मन की बात" कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।